

भारतीय उदारीकरण के गंभीर परिणाम



आज से दो दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में एक शब्द ने बहुत ज़ोर पकड़ा जिसका नाम था - वैश्वीकरण अथवा Globalization। भारत में एक बहुत बड़े वर्ग का मानना था कि भारत को वैश्वीकरण की बहुत आवश्यकता है और उसके बिना भारतीय अर्थव्यवस्था का मज़बूत होना संभव नहीं है। इस सोच का परिणाम यह है कि आज आम आदमी का जीना इस देश में मुश्किल होता जा रहा है। क्या है वैश्वीकरण की सच्चाई? प्रस्तुत लेख भाई राजीव दीक्षित जी के एक भाषण का लिखित स्वरूप है जिसमें मुख्य बिंदुओं की संक्षेप में चर्चा की गई है। आप इस व्याख्यान को श्रद्धेय भाई राजीव जी के श्रीमुख से नीचे दिए गए लिंक पर भी सुन सकते हैं।

ऑडियो लिंक: https://docs.google.com/file/d/0B8n_36gK-KF4N1dBZE1EdVhSb1k/edit?usp=sharing

भारत में वैश्वीकरण का ज़ोर 1991 से बढ़ना आरम्भ हुआ। इससे दो दशक पहले से दक्षिण अमरीका और कुछ अन्य गरीब देशों में इस शब्द ने ज़ोर पकड़ा। वैश्वीकरण का अर्थ होता है अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी बाज़ार के लिए खोलना ताकि विश्व के अन्य देश उसमें घुसकर व्यापार कर सकें। भारत में वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री कहते थे कि इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, विदेशी कंपनियाँ देश में आएंगी तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा, विदेशी निवेश बढ़ेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, उद्योगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा आदि। भारत में वैश्वीकरण को लाने का श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को, जो तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री थे। उनका कहना था कि भारत को globalize करने के लिए हमको अपने रूप की कीमत डॉलर और बड़ी मुद्राओं के सापेक्ष गिरानी पड़ेगी। एक दिन मुद्रा का अवमूल्यन करने के बाद कहा गया कि अब और अवमूल्यन नहीं होगा लेकिन अगले ही दिन फिर अवमूल्यन कर दिया गया। फिर इन्होंने कहा कि अभी हमें थोड़ा और globalize होना है तो इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी जाए। वह भी हो गया और सरकार जो विदेशी माल के आयात पर कर लगाती थी, उसको माफ़ कर दिया गया! फिर कहा कि अभी हम पूरे globalize नहीं हुए हैं तो इसके लिए विदेशी वित्त संस्थानों को भारत में लाकर स्थापित करना होगा तभी हम सही मायनों में globalize होंगे। वो भी कर दिया! इतनी गिरावट के बाद परिणाम तो सुखद होने चाहिए क्योंकि उसी के लिए इतना ढोल पिट रहा था।

संसद में एक दिन सरकार से पूछा गया कि भारत में 1991-1997 के मध्य वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप कितना विदेशी निवेश आया है? इस पर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी का कहना था कि सरकार ने इन 6 सालों में 94000 करोड़ के विदेशी निवेश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। किन्तु यह पूर्ण उत्तर नहीं था। सवाल यह था कि भारत में कितना धन आया है न कि कितने डॉलर के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं! इस पर वित्त मंत्री घबरा गए और कुछ नहीं बोले। जब सभी सांसदों का चाप पड़ा तो उन्हें कहना पड़ा कि 1991 से लेकर 1997 तक भारत में केवल और केवल 19700 करोड़ का ही विदेशी निवेश वास्तव में आया है! उस समय भारत की GDP 8 लाख करोड़ रुपये की थी और हमारी राष्ट्रीय बचत (जो पैसा आम जनता और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय बचाते हैं) इसका 24% अर्थात् लगभग 2 लाख करोड़ रुपये थी। इसका अर्थ है कि छह सालों में 12 लाख करोड़ तो हम खुद ही बचा रहे हैं तो ऊपर के 19700 करोड़ के लिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट क्यों की? अगर हम 12 लाख करोड़ बचा सकते हैं तो 20000 करोड़ रुपये के लिए हमने अपनी पगड़ी गिरवी क्यों रखी? परंतु इन सब के लिए नीतियाँ बनानी पड़ती हैं जिसके लिए संविधान में वित्त मंत्री को रखा गया है। लेकिन वित्त मंत्री अपने पैरों पर देश को खड़ा करने के बजाय देश को विदेशी बैसाखियों के भरोसे छोड़ने के लिए नीतियाँ बनाते हैं। आखिर क्यों?

94000 करोड़ की पूँजी का झांसा देकर जो 19700 करोड़ की चिल्लर एक देश में आई वो भी किसी काम की नहीं थी क्योंकि इसमें से अधिकांश पैसा सट्टा बाज़ार में लगा हुआ था। यह पैसा कभी भी औद्योगिक कार्यों में नहीं लगता।

शेयर बाज़ार बहुत ही सरल सिद्धांत पर चलता है। जिस शेयर को खरीदा जाता है, उसके दाम बढ़ते हैं और जिस शेयर को बेचा जाता है, उसके दाम गिरते हैं। विदेशी कंपनियाँ बहुत भारी निवेश के साथ शेयर खरीद लेती हैं जिससे उस शेयर के दाम में बढोत्तरी होती है। उसके बाद टीवी चैनल पर कुछ बुद्धिजीवी माने जाने वाले लोग बैठकर विवेचन करते हैं कि यह शेयर अच्छा है इसे खरीद लें। आम आदमी को लगता है कि यह शेयर बहुत अच्छा जा रहा है और वह अपनी खून पसीने की कमाई उस शेयर की खरीद में झोंक देता है। यह सब देख कर कई हज़ार लोग अपना पैसा लेकर पहुँच जाते हैं उस शेयर को खरीदने के लिए। इस तरह जब हज़ारों लोगों का पैसा उस शेयर के बढे हुए दाम को और बढ़ा देता है तो ये विदेशी कंपनियाँ अपना पैसा उस शेयर से खींच लेती हैं जिससे उस शेयर का दाम रातों रात जमीन पर आ गिरता है क्योंकि उस शेयर में सबसे अधिक निवेश इन कंपनियों का ही होता है! आम आदमी के हिस्से में आती है केवल बर्बादी! यह खेल रोज़ इस बाज़ार में चलता है और रोज़ हज़ारों लोग बर्बाद होते हैं। जिसे आज फायदा होता है, वह और पैसे लगाता है और अंत में पहले से अधिक कंगाल हो कर निकलता है। फायदा होता है तो केवल विदेशी वित्तीय संस्थानों का जो बाज़ार को अपने हिसाब से चलाती हैं और इन्हें licence मिलता है वित्त मंत्रालय से! अगर समग्र दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी निवेश लगता है और देश की राष्ट्रीय बचत इन बाज़ारों के रास्ते विदेशों में चली जाती है क्योंकि जो आम आदमी इस बाज़ार में घुसता है वह अपनी जमा की हुई पूँजी ही लगाता है।

1997 में जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह से पूछा गया कि चलो माना भारत में बीस हज़ार करोड़ का विदेशी निवेश आ भी गया तो 1991 से लेकर अब तक भारत का कितना पैसा बाहर जा चुका है? जवाब था 34000 करोड़ रुपये!

UNCTAD (United Nations Commission for Trade Development) की

1995-96 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमीर देशों से गरीब देशों में जो धन गया, जिसमें विदेशी सहायता, ऋण, निवेश आदि शामिल था, वो था 500 बिलियन डॉलर और जो गरीब देशों से अमीर देशों में धन गया वो था 725 बिलियन डॉलर! अमीर देश कभी भी गरीब देशों की मदद नहीं करते। जिस समय भारत में विदेशी पूँजी लाने की बात चल रही थी, उस समय अमरीका और यूरोप में आर्थिक मंदी का दौर था। यही हाल आज से तीन वर्ष पहले भी था जब भारत में कुछ और विदेशी कंपनियों को घुसाया गया जबकि अमरीका में भारी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। एक सीधा सा प्रश्न है कि जिसके खुद के घर में खाने के लिए रोटी नहीं वो आपके घर की छत कैसे डलवा सकता है? जिस देश में आर्थिक मंदी चल रही है, वह पहले अपने देश को मंदी से निकालेगा या आपके देश में निवेश करेगा? यही कारण है कि 20000 करोड़ लाकर 34000 करोड़ अगर छह वर्ष में निकाल लिए गए। ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि कौन किसे आर्थिक सहायता पहुँचा रहा है! आज तो पहले से भी कहीं ज्यादा MNC भारत में घुस चुकी हैं, तो सोचिए कि बीते 16 वर्षों में कितनी लूट हुई होगी और हो रही है? वो तो शुक्र है कि वालमार्ट अभी तक नहीं आया लेकिन सरकार पूरा जोर लगा रही है उसे भारत में घुसाने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो रोटी भी आपको अमरीकियों की दया पर मिलेगी!

भारत के वित्त मंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। इसके अलावा भी ये भारत में तीन सरकारों के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। साउथ कमीशन के ये सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इसी साउथ कमीशन में इन्होंने एक आंकड़ा दुनिया के सामने रखा था कि 1986 से 1989 तक अमीर देशों से कितनी पूँजी आई एशिया के गरीब देशों में और यहाँ से कितनी पूँजी गई वापिस अमीर देशों के पास। यह इन्हीं का आंकड़ा था कि इन तीन वर्षों में अमीर देशों से 215 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश; विदेशी सहायता,

ऋण, निवेश आदि सब मिलाकर; एशिया के गरीब देशों में आया तथा 345 बिलियन डॉलर इन देशों से विदेशों में वापिस गया! यह आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया था यह बताने के लिए कि विदेशी नीतियाँ वास्तव में गरीब देशों के लिए क्या हैं क्योंकि ये उस समय दक्षिण एशिया के इस ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल थे। एक महान अर्थशास्त्री होने के नाते इन्हें आँकड़े तो समझ आते ही होंगे अगर इन्हें हम जैसे लोग समझ सकते हैं! परंतु ऐसा कैसे हो गया कि एक व्यक्ति जो वित्त मंत्री बनने से पहले कुछ कहता हो, वित्त मंत्री बनने के बाद एकदम 'यू टर्न' ले ले तथा प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे देश को उसी 'यू टर्न' की दिशा में ले चले?

बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री बनने से पहले ही मई 1991 में फ्रांस के एक अखबार 'Le Monde' में यह घोषणा हो चुकी थी कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनेंगे जबकि चुनाव अभी अपनी प्रक्रिया में ही थे! सवाल यह है कि भारत में कौन वित्त मंत्री बनेगा या बनेगी इसका निर्णय बाहर के लोग लेंगे? यह ऐसे ही नहीं हुआ, इसके गहरे तार जुड़े हैं और तार ये हैं कि मनमोहन सिंह विश्व बैंक के लिए काम करते थे औपचारिक रूप से और उसी विश्व बैंक ने इन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाया अनौपचारिक रूप से! एक बार जब वित्त मंत्री के पद से मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देना चाहा क्योंकि इनकी गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ती जा रही थी और कांग्रेस के खेमे के मंत्री रोष में थे क्योंकि उनका वोट बैंक छिन रहा था, तो विश्व बैंक के चेयरमैन का भारत के प्रधान मंत्री को एक सन्देश भेजा गया कि आप इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे! पी चिदंबरम तो इनसे भी दो कदम आगे हैं। जब इन्होंने एक बार इस्तीफा देने की धमकी दी, तब भी एक प्रेस कांफ्रेंस में विश्व बैंक के चेयरमैन का बयान आया कि अगर चिदंबरम हट गए तो वैश्वीकरण का क्या होगा? अक्टूबर 1996 में चिदंबरम लन्दन गए

और वहाँ की एक प्रेस कांफ्रेंस में कहकर आए कि “आपने भारत को 200 सालों तक लूटा है, आप पूँजी लेकर फिर भारत चलिए और अगले 200 सालों तक और रहिये। आपके लिए बहुत बड़े पुरस्कार इंतज़ार कर रहे हैं!”

(http://www.business-standard.com/article/economy-policy/fms-invitation-to-mnacs-raises-swadeshi-hackles-197022701116_1.html)

क्या कहेंगे आप ऐसे व्यक्ति को?

इस वैश्वीकरण के नाम पर मनमोहन सिंह ने इतने शर्मनाक समझौते किए हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते! कनाडा की एक कंपनी से समझौता किया गया कि वह अपना atomic waste भारत में लाकर डंप करेंगे। भारत से पहले वे बंगलादेश के पास गए थे जिसने इसकी इजाज़त नहीं दी क्योंकि वे जानते थे कि इसके क्या परिणाम निकलेंगे। पेप्सी के साथ एक संधि हुई जिसमें यह तय किया गया कि प्रतिवर्ष पेप्सी 10 करोड़ मीट्रिक टन रासायनिक कचरा भारत में लाकर डंप करेगी। स्वर्ग जैसे सुन्दर प्रदेश केरल के एक मनोहर द्वीप को उसके लिए चुना गया जिसकी इजाज़त भारत सरकार से मिली। अमरीका की एक कंपनी Kelvinator, जो फ्रिज बनाती थी, को भारत में आकर फ्रिज बेचने की आज़ादी मिली। आप शायद जानते हों कि इस कंपनी से पहले भारतवासी फ्रिज का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि इसकी कभी हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। विदेशों में बासा खाना खाने की परंपरा रही है जिसकी वजह से उनका तंत्र फ्रिज की मांग करता है। इस फ्रिज की वजह से CFC (Chloro Floro Carbon) का रिसाव होता है जो वातावरण के लिए अच्छा नहीं होता और ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण घटक है। अमरीका में refrigeration के क्षेत्र में तकनीक बदली तो उन्होंने सोचा कि पुरानी तकनीक कहाँ चिपकाई जाए। इसके लिए भारत से बढ़िया विकल्प नहीं था। तब से भारत में फ्रिज हर घर में पाया जाता है तथा साथ ही कब्ज, आलस्य और वात रोग भी!

इन सभी समझौतों से ऊपर सबसे घिनौना समझौता जो किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा, वह था हॉलैंड के सूअरों का मल भारत में लाकर उपयोग करना! भारत सरकार ने तर्क दिया कि इन सूअरों का मल अच्छा होता है क्योंकि ये सोयाबीन खाते हैं। सोयाबीन कहाँ से जाता है? भारत के मध्य प्रदेश से! क्या आपको पता है, लगातार 10 वर्ष तक सोयाबीन की खेती करने के बाद जमीन बंजर हो जाती है? इस सोयाबीन को यूरोप का कोई भी देश, खासकर हॉलैंड अपने यहाँ नहीं उगाता क्योंकि उन्हें अपनी जमीन की चिंता है लेकिन भारत सरकार से संधि के बाद यहाँ सोयाबीन की खेती ताबड़ तोड़ शुरू कर दी गई और उसे हॉलैंड भेज कर वहाँ से सूअरों का मल भारत में आने लगा। जब इन सब कारणों और सोयाबीन की वजह से भारतीय कृषि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के साथ राजीव दीक्षित जी ने केस कोर्ट में दायर किया तो मनमोहन सिंह फँस गए और उन्हें यह संधि हॉलैंड के साथ तोड़नी पड़ी! प्रश्न यह है कि क्या इस देश में एक भी विभाग ऐसा नहीं है जो इस तरह के समझौतों पर नज़र रख सके? या फिर उन्हें जान बूझकर बनने नहीं दिया जाता ताकि खुलकर देश को लूटा जा सके?

वास्तव में उदारीकरण भारतवासियों के लिए नहीं विदेशियों के लिए किया गया है ताकि वे हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण कर सकें। उदारीकरण की इस नीति को भारत में New Economic Policy का नाम दिया गया जो कि एकदम झूठ है! यह वास्तव में उदारीकरण नहीं उपनिवेशीकरण है जिसका दंश हम पहले भी झेल चुके हैं और जिसमें से निकलने के लिए न जाने कितने लाख लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी! अंग्रेज़ एक शब्द के बहाने भारत में व्यापार करने घुसे थे और वह शब्द था 'Free Trade'। इस अकेले शब्द ने

भारत के उद्योगों और अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था तथा भारत को एक गरीब देश बना छोड़ा था! उन्हें भी यहाँ के राजाओं से कुछ विशेषाधिकार मिल गए थे जिनके बल पर उन्होंने भारत को जमकर लूटा। उसका एक उदाहरण है Income Tax Act जो भारत में सन 1844 में लागू हुआ था। पहली बार में ही यह 97% था जिसकी वजह से भारतीय वस्तुएं महँगी हुईं और विदेशी चीज़ें सस्ती मिलने लगीं क्योंकि उन पर कोई कर नहीं लगाया जाता था! आज के भारत में कितनी ही विदेशी कंपनियों को टैक्स हॉलिडे तक दे दिया जाता है लेकिन अगर एक आम आदमी टैक्स न दे तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ता है! जो विश्व बैंक भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र में अपना चुना हुआ व्यक्ति वित्त या प्रधानमंत्री बना सकता है तो समझ लीजिए की देश की सुरक्षा और अस्मिता कितने खतरे में है! अंग्रेज़ों ने सारे कानून भारत को लूटने के लिए बनाये थे जिन्हें आज़ादी मिलने के बाद बदल देना चाहिए था लेकिन आज भी ये सारे कानून बदस्तूर जारी हैं क्योंकि नीयत आज भी वही है, 'भारत का शोषण'!

ये हम ही हैं जो इन लोगों को वोट देते हैं। अपने लिए न सही लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी सरकार लेकर आयें! कांग्रेस को भारत से मार भगाएँ!!

वंदे मातरम...